अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय
COVID-19 आजीविका सर्वेक्षण

झारखंड (ग्रामीण)

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोज़गार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने प्रदान के साथ मिलकर झारखंड के ४५८ उत्तरदाताओं [1] का एक विस्तृत फ़ोन सर्वेक्षण किया।

उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि के द्वारा किया गया था जिससे उनके कार्य और स्थान में विविधता सुनिश्चित की जा सके।यह प्रतिदर्श (सैंपल) राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

यहाँ प्रस्तुत डाटा ३० अप्रिल, २०२० और १३ मई, २०२० के बीच एकत्र किया गया था। यह सर्वेक्षण परिणाम राज्य-स्तरीय संक्षिप्त जानकारी की एक श्रृंखला का हिस्सा है। विस्तृत जानकारी *cse.azimpremjiuniversity.edu.in* पर उपलब्ध है।

1 हमने झारखंड में बहुत कम शहरी परविारों का साक्षात्कार लयिा जो इस वशि्लेषण का हसि्सा नहीं हैं।

मुख्य निष्कर्ष

५८%
श्रमिकों ने अपना रोजगार खोया है।

६५%
तक गैर-कृषि स्व-रोज़गार और दिहाड़ी मजदूरों की औसत कमाई गिर गई।

२७%
परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

७७%
परिवारों ने बताया कि पहले की तुलना में वो अब कम खाना खा रहे हैं।

१० मैं से ८
वंचित परिवारों को राशन मिला।

४६%
वंचित परिवारों को कम से कम एक नकद अंतरण (ट्रांसफर) मिला।

राहत उपायों की घोषणा

एसएमएस के माध्यम से सर्वेक्षण उत्तरदाताओं को राहत उपाय की जानकारी भेजी गई थी।

केंद्रीय स्तर

* हर परिवार को प्रति व्यक्ति ५ किलो अनाज (चावल/गेहूँ) और प्रति परिवार १ किलो दाल अप्रेल से जून 2020 तक हर महीने मुफ्त दिया जाएगा । यह नियमित राशन के अतिरिक्त है जो उन्हें मिलता रहेगा।
* अप्रेल से जून 2020 तक हर महीने महिला जन धन खाता धारकों के खाते में Rs 500 की राशि जमा की जाएगी।
* पीएम-किसन (रु २०००) योजना की प्रथम किश्त (Rs2000) अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में दी जाएगी।

राज्य स्तर

* अप्रैल में PHH कार्ड धारक परिवारों के हर सदस्य को 10 किलो अनाज, रु 1 प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा।
* मई में PHH परिवारों के हर सदस्य को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा।
* जून में PHH परिवारो के हर सदस्य को 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 किलो अनाज रु 1 प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा।
* अप्रैल में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड धारक परिवारों को 70 किलो अनाज रु 1 प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा।
* मई में AAY परिवारों को 10 किलो अनाज प्रति सदस्य मुफ्त मिलेगा।
* जून में AAY परिवारों को 35 किलो अनाज प्रत्येक कार्ड पर रु 1 प्रति किलो के हिसाब से और 5 किलो अनाज प्रति सदस्य मुफ्त मिलेगा।
* जिन परिवारों के राशन कार्ड आवेदन लंबित हैं सरकार उन्हें रु 1 प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो चावल देगी।
* राज्य के सभी जिलों में थाना स्तर पर दाल भात केंद्र खोले जायेंगे जहाँ भोजन रु 5 प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जायेगा।
* मार्च और अप्रैल की पेंशन एडवांस में दे दी जायेगी।
* आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा खाना बच्चो के घर भेजा जायेगा।

Source : covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures

अनुशंसाएँ

* पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए।
* दो महीने के लिए कम से कम रु 7000 का नकद हस्तांतरण (ट्रांसफर) दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए बड़े हस्तांतरण की आवश्यकता है।
* नकद हस्तांतरण की पहुंच का विस्तार करने के लिए मनरेगा, पीएम उज्जवला, पीडीएस और स्थानीय पंजीकरण से जानकारी का उपयोग करें।
* शहरी गरीबों के लिए कार्यक्रमों पर जोर देने की जरूरत है।
* मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की जरूरत है।

आजीविका पर प्रभाव

यह भाग तालाबंदी के चलते काम और कमाई पर पड़े असर को समझने की कोशिश करता है । तालाबंदी लागू होने के बाद के रोज़गार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है।

चित्र १: जिन श्रमिकों ने रोजगार खोया है (फरवरी गतिविधि की स्थिति के अनुसार) (%)

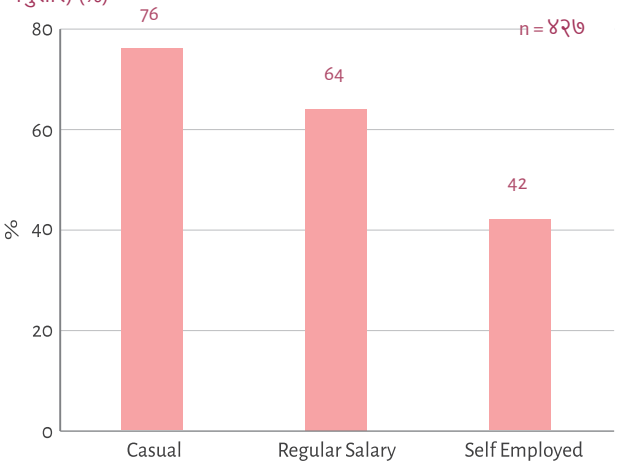

५८% श्रमकिों ने बताया कि उन्होंने तालाबंदी के दौरान अपना रोजगार खोया है।

७६% दहिाड़ी श्रमकिों ने अपनी नौकरी खोदी, वह सबसे ज़्यादा प्रभावति हए हैं।

८९% कसिानों ने बताया कि वह अपनी उपज को सही कीमत पर बेचने में असमर्थ हुए।

४२% वेतनभोगी मज़दूरों ने बताया कि उन्हें उनके वेतन का भुगतान नहीं कयिा गया या उन्हें लॉकडाउन के दौरान कम वेतन मलिा।

दहिाड़ी श्रमकिों और स्व-नयिोजति गैर कृषि श्रमकिों की औसत साप्ताहकि कमाई में ६५% की गरिावट।

"लॉकडाउन के कारण, सभी काम बंद हो गए हैं। हमे चावल मिल रहा है लेकिन हमें तेल, साबुन आदि खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इस कारण मै मनरेगा का काम उठाना चाहती हूं । नकदी फसल की खेती मैं इस समय उलझने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उपज बेची नहीं जा रही है।."
(महिला, ३२, दिहाड़ी मज़दूर)

चित्र २ : श्रमिक जिन्होंने अपना रोज़गार खो दिया है (%)

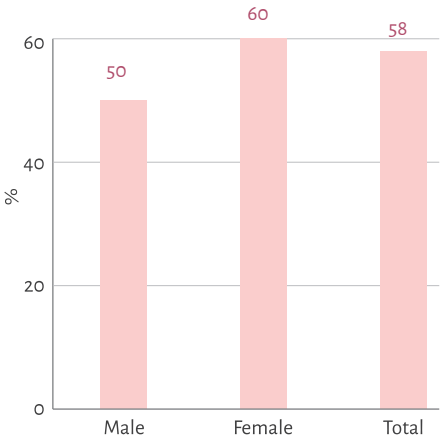

घरों पर प्रभाव

यह भाग यह देखता है परिवारों पर, खासकर उनके भोजन के सेवन अथवा कर्ज़े और बचत की स्तिथि पर, तालाबंदी के कारण क्या प्रभाव पड़ा।

चित्र ३: फ़रवरी के महीने में गतिविधि कि स्तिथि के अनुसार पहले कि तुलना से कम भोजन लेने वाले परिवार (%)

n = ४५८

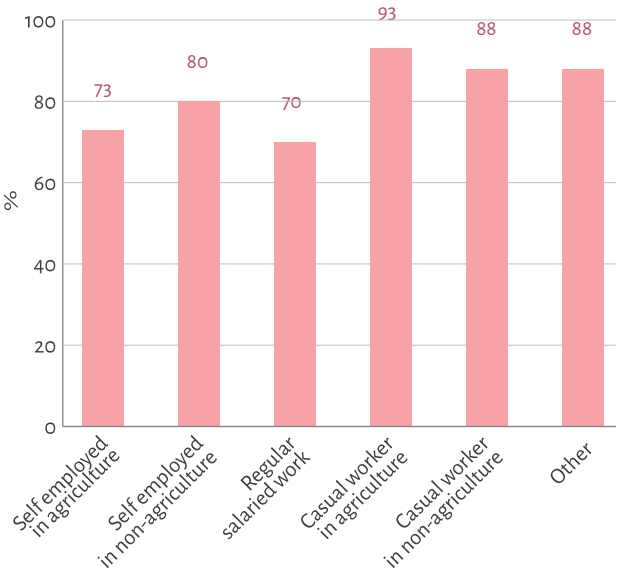

७७% परिवारों ने बताया की तालाबंदी के दौरान उन्होंने पहले कि तुलना में कम भोजन का सेवन कयिा।

९३% कृषि श्रमिकों ने भोजन के सेवन में कमी की सूचना दी।

२७% परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

सामान्य (११%) और ओबीसी (२२%) परिवारों की तुलना में, एससी / एसटी परिवारों (२९%) परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

हर पांच मैं से एक से अधकि परविारों को इस तालाबंदी के परणिामस्वरूप ऋण लेना पड़ा।

१० मैं ८ परविार अगले महीने का करिाया नहीं दे सकते।

चित्र ४: वंचित घरों कि स्तिथि, भोजन सेवन और बचत के संबंध में (%)

n = ३८९

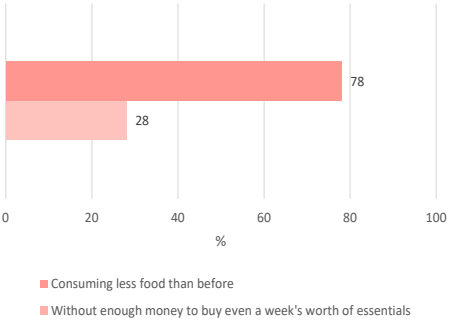

राहत योजनाओं की पहुँच

यह भाग सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों की पहुंच और प्रभाव का अध्ययन करता है। हम राशन की उपलब्धता, लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण और कमजोर परिवारों को मिलने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

चित्र ५: वंचित परिवार जिन्हे तालाबंदी के दौरान राशन और जन धन ट्रांसफर मिला (%)

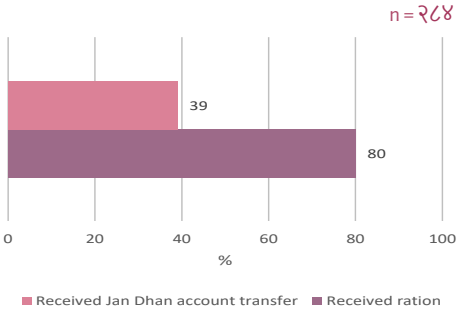

१० मैं से ८ वंचति परविारों को राशन मलिा।

५६% वंचति परविारों के पास जन धन खाता नहीं था, परन्तु जनि के पास खता था उनमे से ९०% को नकद हस्तांतरण प्राप्त हुआ।

४६% वंचति परविारों को कम से कम एक नकद हस्तांतरण प्राप्त होने की सूचना मलिी।

केवल १६% कसिानों को PM-KISAN स्थानांतरण प्राप्त हुआ।

" मैं मनरेगा के तहत काम करना चाहती हूं, लेकिन कोई काम उपलब्ध नहीं है।पिछले साल की मजदूरी अभी भी लंबित है।"
(महिला, ४०, आकस्मिक कार्यकर्ता)

सर्वे कवरेज

२५% प्रतिवादी पुरुष थे और ७५% महिलाएं थीं।

६१% प्रतिवादी हिंदु थे, ईसाइ १२% और ३% मुसलमान।

९०% परिवार वंचित थे यानी उन्होंने फरवरी में १०,००० रुपये से कम कमाए।

५७% प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति के थे, और ११% अनुसूचित जाति के थे।

चित्र ६: फरवरी के महीने में उत्तरदाताओं की गतिविधि की स्थिति (%)

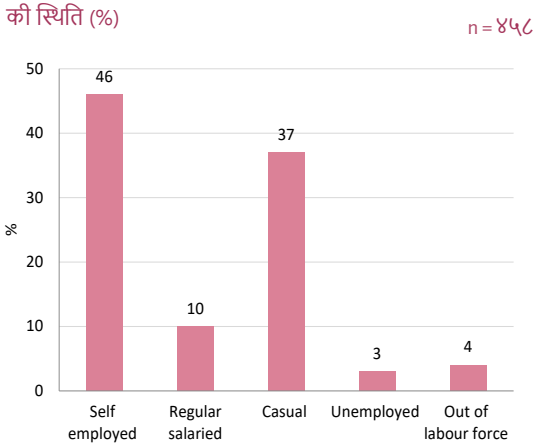

राज्य में हो रहे अन्य सर्वेक्षणों के परिणाम

* भोजन के अधिकार अभियान द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि बहुत कम जिलों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित १० किलोग्राम खाद्यान्न मिला है।

* हेचल गांव में सोसाइटी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि कोई भी किसान अपनी किसी भी उपज को नहीं बेच पा रहा है और भारी नुकसान उठा रहा है।

* आईआईटी-दिल्ली (ग्राम वाणी), द रोड स्कॉलरज और केंद्र नीति अनुसंधान द्वारा आयोजित शोध में अन्य राज्यों के साथ-साथ दिल्ली पर पड़े कोरोना के प्रभाव की भी व्याख्या की गयी है।

देश भर में किए गए विभिन्न कोविड़-19 सर्वेक्षणों और अध्ययनों के संकलन के लिए कृपया देखें: *cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys*

सवाल के लिए: **Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University**
cse.azimpremjiuniversity.edu.in | cse@apu.edu.in